

ग्रसाधः रण

EXTRAORDINARY

भाग **II—खण्ड** 3—उपसण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 295] मई विस्ली, शनिवार

मई विस्ली, शनिवार, नयम्बर 16, 1974/कार्तिक 25, 1896

No 295] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 16, 1974/KARTIKA 25, 1896

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के उप में रखा जा सके 1.

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November 1974

G.S.R. 659(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 359 of the Constitution, the President hereby declares that—

(a) the right to move any court with respect to orders of detention which have already been made or which may hereafter be made under section 3(1)(c) of the Maintenance of Internal Security Act, 1971 as amended by Ordinance 11 of 1974, for the enforcement of the rights conferred by article 14, article 21 and clauses (4), (5), (6) and (7) of article 22 of the Constitution, and

(b) all proceedings pending in any court for the enforcement of any of the aforesaid rights with respect to orders of detention made under the said section 3(1)(c),

shall remain suspended for a period of six months from the date of issue of this Order or the period during which the Proclamation of Emergency issued under clause (1) of article 352 of the Constitution on the 3rd December, 1971, is in force, whichever period expires earlier.

2. This order shall extend to the whole of the territory of India.

[No. 11/16011/14/74-S&P(D.II)]

N. K. MUKARJI, Secy.

गृह मंत्रालय

ग्रधिभूचना

नई दिल्ली, 16 नवन्बर, 1974

सा० सा० ति० 659(भा).---संविधान के अनुच्छेद 359 के खंड(1) द्वारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतदृहारा उद्दर्शयणा करते हैं कि----

- (क) 1974 के घन्यादेश 11 के घ्रधोन संशोधित म्रान्नित्क सुरक्षा मनुरक्षण म्रधिनियम, 1971 की धारा 3(1)(ग) के प्रधीन नजरबन्दी के निए जारी किए जा चुके या इसके बाद जारी किए जाने वाले भादेशों के सम्बन्ध में, संविधान के म्रनुच्छेद 14, भनुच्छेद 21 भीर मनुच्छेद 22 के खंड (4), (5), (6) भीर (7) द्वारा प्रदत्त मधिकारों के भवतंन करने के लिए किसी न्यायालय में जाने का मधिकार, भीर
- (ख) उपर्युक्त धारा 3(1)(ग) के ग्रधीन नजरबन्दी के ग्रादेशों के सम्बन्ध में उक्त श्रधिकारों में से किसी श्रधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय में निर्णयाधीन सभी कार्यवाहिया,

इस आदेश के जारी होने की तारीख से छ: मास के लिए या उस धवधि सक निलम्बित रहेगी, जब तक कि 3 दिसम्बर, 1971 को संविधान के अन्-छोद 352 के खण्ड (1) के अधीन जारी की गई आपात्कालीन स्थिति की घीषणा लागू है, इन दोनों में से जो भी धविध पहले समाप्त हो जाए।

2. यह भादेश समस्त भारत में लागू होंगे।

[सं II/16011/14/74-एस० एंड पी० (डी॰ II)]

नि० मुकर्जी, सिचय ।